आर्थिक असमानता एवं ब्रिक्स देश

डा० मधु शर्मा
अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
आर०एस०एस० पी०जी० कॉलेज, पिलखुवा, हापुड़
ईमेलः dr.madhusharma2@gmail.com

सारांश

सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। ब्रेटलैंड कमीशन (1987) के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की सक्षमता से समझौता किए बगैर वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। आय तथा संपत्ति के असमान वितरण की समस्या का संबंध मुख्य रुप से व्यक्तिगत आय के वितरण में विषमताओं से होता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों की आय बहुत अधिक होती है जबकि अधिकतर लोगों की आय बहुत कम है। आर्थिक असमानता व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूह या देशों के बीच आर्थिक अंतर को दर्शाता है। आर्थिक असमानता आय असमानता, धन असमानता या धन अंतर को प्रदर्शित करती है अर्थशास्त्री इसके लिए धन, आय और उपभोग इन तीन मापों का प्रयोग करते हैं। आर्थिक असमानता, विभिन्न समाज, विभिन्न समय, आर्थिक योजनाओं और आर्थिक प्रणालियों के बीच परिवर्तित होती रहती हैं। सबसे अमीर 10 प्रतिशत के पास वैश्विक आय का 40 प्रतिशत तक है जबकि सबसे गरीब 10 प्रतिशत केवल 2 से 7 प्रतिशत के बीच कमाते हैं। यदि हम विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि असमानता को ध्यान में रखें तो असमानता 11 प्रतिशत बढ़ गई है। हाल के दशकों में लगभग हर जगह आय असमानता बढ़ी है, लेकिन अलग–अलग गति से। यह यूरोप में सबसे कम और मध्य पूर्व में सबसे अधिक है। इन बढ़ती असमानताओं के लिए कम आय वालों को सशक्त बनाने और लिंग, नस्ल या जातीयता की परवाह किए बिना सभी के आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता है। आय असमानता के लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। ब्रिक्स के बीच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में कुल असमानताएं 1990 और 2010 के बीच पूर्ण रूप से कम हो गई लेकिन सापेक्ष रूप से बढ़ गई। मातृ मृत्यु दर में पूर्ण असमानताएं 1990 में भारत और रूसी संघ के बीच प्रति

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 10.03.2024
Approved: 15.03.2024

डा० मधु शर्मा

आर्थिक असमानता एवं ब्रिक्स देश

RJPP Oct.23-Mar.24,
Vol. XXII, No. I,

PP. 064-071
Article No. 09

Online available at:
https://anubooks.com/view?file=3566&session_id=rjpp-march-2024-vol-xxii-no1-230

100,000 जीवित जन्मों पर 526 अतिरिक्त मातृ मृत्यु से घटकर 2010 में दक्षिण अफ्रीका और रूसी संघ के बीच प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 266 ऐसी मृत्यु हो गईं। 1990 में, चीन और भारत दोनों में मातृ मृत्यु दर का स्तर 2010 में दर्ज मूल्यों से तीन गुना अधिक था। जब हमने 1990 में शिशु और बाल मृत्यु दर की पूर्ण असमानताओं की जांच की, तो हमने पाया कि– प्रति 1000 जीवित जन्म वहीं 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की 58 अतिरिक्त मौतें हुई और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 87 अतिरिक्त मौतें हुई।

मुख्य शब्द

सतत विकास, आर्थिक असमानता, सापेक्ष गरीबी, एसडीजी।

प्रस्तावना

आर्थिक समानता का तात्पर्य अधिक धन कमाने से ना होकर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति से हम आर्थिक समानता का यह अर्थ नहीं है, कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध हो बल्कि इसका अर्थ यह है कि संपत्ति और धन का उचित वितरण हो जिसमें समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में सारा धन अथवा सारी संपत्ति जमा ना हो जाए इससे समानता का अर्थ लगाया जा सकता कि सभी व्यक्तियों के पास संपत्ति तथा समान धन हो किंतु यह संभव नहीं है साम्यवादी देशों में भी इस सीमा का आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा सकी है सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को कोई हानि नहीं पहुंचाती है।

सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कई अलग–अलग तरीकों से की जा सकती है, लेकिन इसके मूल में विकास का एक दृष्टिकोण है जो एक समाज के रूप में हमारे सामने आने वाली पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक सीमाओं के बारे में जागरूकता के खिलाफ अलग–अलग और अक्सर प्रतिस्पर्धी जरूरतों को संतुलित करता है। अक्सर, व्यापक या भविष्य के प्रभावों पर पूरी तरह से विचार किए बिना, विकास एक विशेष आवश्यकता से प्रेरित होता है। हम पहले से ही देख रहे है कि इस तरह के दृष्टिकोण से गैर–जिम्मेदार बैंकिंग के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट से लेकर जीवाश्म ईंधन–आधारित ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता के परिणामस्वरूप वैश्विक जलवायु में बदलाव हो सकता है। हम जितना अधिक समय तक अस्थिर विकास करते रहेंगे, इसके परिणाम उतने ही अधिक बार और गंभीर होने की संभावना है, यही कारण है कि हमें अब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। परंतु यहा एक बात उल्लेखनीय है कि सतत विकास की अवधारणा केवल पर्यावरणीय समस्याओं तक सीमित नहीं है वरन, हमारी पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर रहना सतत विकास के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। ऐसा न करने का एक निहितार्थ जलवायु परिवर्तन है। लेकिन सतत विकास का फोकस सिर्फ पर्यावरण से कहीं अधिक व्यापक है। यह एक मजबूत, स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के बारे में भी है। इसका मतलब मौजूदा और भविष्य के समुदायों में सभी लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यक्तिगत भलाई, सामाजिक एकजुटता और समावेशन को बढ़ावा देना और समान अवसर पैदा करना है।

सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत् विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किये गए हैं। इस एजेण्डे में वैश्विक साझेदारी हेतु दुनिया के सभी विकसित एवं विकासशील देशों से 17 प्रमुख

लक्षित बिन्दुओं पर साझा कार्यवाही का एक जरूरी आह्वान किया गया है। ऐसा मानना है कि गरीबी और अन्य अभावों को समाप्त करने के लिए उन रणनीतियों को साथ–साथ चलाया जाना चाहिए जो स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करें, असमानता को कम करें और आर्थिक विकास को गति दें। ऐसे ही साझा प्रयास जलवायु परिवर्तन से निपटने और हमारे महासागरों और जंगलो को संरक्षित करने के लिए काम करते हुए भी किया जाना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य या वैश्विक लक्ष्य 17 परस्पर जुड़े उद्देश्यों का एक संग्रह है जो वर्तमान और भविष्य में व्यक्तियों के लिए और पृथ्वी ग्रह के लिए शांति और समृद्धि के लिए साझा ब्लूप्रिंट तैयार करता है, जिन्वों 17 सतत विकास लक्ष्य बिन्दुओं में विभक्त किया गया है। यह एजेंडा दुनिया के लोगों और हमारे ग्रह की समृद्धि के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। यह व्यापक स्वतंत्रता में सार्वभौमिक शांति को मजबूत करने का भी प्रयास है। दुनिया भर के देशों में अत्यधिक गरीबी सहित सभी रूपों और आयामों में गरीबी उन्मूलन सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती और सतत विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। सभी देश और सभी हित धारक सहयोगात्मक साझेदारी में कार्य करते हुए इस योजना को लागू कर लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सतत विकास के लक्ष्य मानव जाति को गरीबी और अभाव के अत्याचार से मुक्त करने और अपने ग्रह को स्वस्थ और सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिन 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों की घोषणा की गई थी, वे इस नए सार्वभौमिक एजेंडे के पैमाने और महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करते हैं। ये लक्ष्य एकीकृत और अविभाज्य हैं और सतत विकास के तीन आयामों (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय) को संतुलित करते हैं। सतत् विकास लक्ष्य वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में '2030 सतत् विकास हेतु एजेंडा' के तहत सदस्य देषों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात् एसडीजी (Sustainable Development Goals - SDGs) तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किये गए हैं।

'पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग' (1983) के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट (1987) के अनुसारदृ 'आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत् विकास है।'

MDGs की अवधि 2015 में खत्म हो गई। पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव विकास हेतु। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 (17 विकास लक्ष्य)

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिष्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
9. लचीले बुनियादी ढाँचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा।

10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।
14. स्थायी सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव–विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
16. सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।
17. सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

SDG 1 जनवरी, 2016 से प्रभाव में आ गए तथा यूएनडीपी की निगरानी व संरक्षण में ये अगले 15 सालों तक प्रभावी रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख SDG, लक्ष्य प्राप्ति कार्य करने वाली संस्था यूएनडीपी विश्व के 170 देशों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर नजर रखेगी।

यूएनडीपी का प्रमुख लक्ष्य इन देशों में गरीबी को खत्म करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा परिवर्तन पर कार्य तथा आर्थिक समानता प्राप्ति आदि पर ज्यादातर केंद्रित रहेगा। SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सभी लोगों को आपसी सहयोग से काम करना होगा।

सतत् विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य विश्व से गरीबी को पूर्णतः खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना है। भारत को भी गंभीरता से इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिये।

जब समाज का एक अंग जीवन स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तथा निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है तो कहा जा सकता है कि समाज में व्यापक गरीबी है। अर्थात् गरीबी से आशय उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है गरीबी, बेरोजगारी तथा आय असमानता में तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें से किसी भी एक की उपस्थिति तीनों स्थितियों को उत्पन्न कर सकती हैं। सभी समाजों में गरीबी को परिभाषित करने के प्रयास किए गए परंतु इन सबका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी की धारणा भारत से बिल्कुल ही भिन्न होगी क्योंकि अमेरिका में आम नागरिक कहीं अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर रह रहा है। भारत में गरीबी की सामान्यतः स्वीकृत परिभाषा उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर पर बल देती है।

सापेक्ष गरीबी

विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विशमता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न आय वर्ग के संबंध में आय संबंधी अनुमान लिए जाते हैं तथा जनसंख्या के निचले 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत आय समूह की तुलना ऊपरी 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत आय समूह के साथ की जाती है तथा इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक गरीबी की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं।

निरपेक्ष गरीबी

सापेक्षिक गरीबी से इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि गरीब लोगों की मात्रा क्या है इस कमी को दूर करने के लिए निरपेक्ष गरीबी का अध्ययन किया जाता है। गरीबी की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग स्रहके प्रथम महानिदेशक आर वायड ने 1945 में किया। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। उदाहरण के लिए जिन लोगों की आय 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन देने वाली आय से कम होगी उन्हें हम गरीब कहते हैं।

भारत में गरीबी का निर्धारण

भारत में आठवी योजना में कैलोरी मापदण्ड। के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। 2400 कैलोरीग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2100 कैलोरी को शहरी क्षेत्र में आधार स्वीकार किया गया तथा 1973–1974 में मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय लिया गया। विष्व बैंक विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में 1 डॉलर प्रतिदिन आय को मानक के मानता था अब वह 1.25 डॉलर प्रतिदिन आय को मानक के रूप में मानता है।

राष्ट्रों के मध्य आर्थिक असमानता

घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर निर्धनता के स्तर एवं सघनता का मापन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं विवादास्पद मुद्दा रहा है। अर्थशास्त्रियों एवं विषेशज्ञों के स्तर पर अभी तक ऐसी कोई भी सर्वमान्य विधि अथवा फॉर्मूला अथवा उपागम विकसित नहीं किया जा सका है, जो देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुरूप अधिक–से–अधिक सटीक तथा बृहत् स्तर पर स्वीकार्य हो।

वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 1.25 अमरीकी डॉलर की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय (क्रय शक्ति समता के आधार पर) को निर्धनता रेखा मानता है। इस दृष्टि से 2010 में पूर्वी एशिया एवं प्रशान्त में 12.5 प्रतिशत, यूरोप एवं मध्य एशिया में 0–7 प्रतिशत, लेटिन अमरीका एवं कैरेबियाई द्वीपों में 5.5 प्रतिशत, मध्य–पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में 2.4 प्रतिशत, दक्षिण एशिया में 31.0 प्रतिशत तथा उपसहारा अफीका में 48.5 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी) अर्थव्यवस्थाओं पर 2011 में जारी अपनी रिपोर्ट में यह स्थापित किया है कि भारत में 42 प्रतिशत आबादी की प्रतिदिन आय 1,25 डालर है। भारत में गत तीन दशकों में आर्थिक असमानतायें बढ़ी हैं, विभिन्न वर्गों की आय के बीच अन्तराल बहुत अधिक बढ़ा है। जहाँ ब्राजील, इण्डोनेशिया और अर्जनटीना में विगत कुछ वर्षों में धनी तथा गरीब के बीच विषमता में कमी आयी है वहीं चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका तथा रूस में इसमें वृद्धि हुयी है। तकनीकी विकास का फायदा केवल अधिक प्रशिक्षित लोगों को मिला है।

आर्थिक असमानता

सतत विकास लक्ष्य 10 का उद्देश्य देशों के भीतर और मध्य में आर्थिक असमानता को कम करना है। यह एसडीजी आय के साथ–साथ किसी देश के भीतर उम्र, लिग, विकलांगता, नस्ल, जातीयता, मूल, धर्म या आर्थिक या अन्य स्थिति पर आधारित असमानताओं को कम करने का आह्वान करता है। यह लक्ष्य देशों के बीच असमानताओं को भी संबोधित करता है, जिसमें प्रतिनिधित्व, प्रवासन और विकास सहायता से संबंधित असमानताएं भी शामिल हैं। समुदाय ने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सबसे कमजोर राष्ट्र सबसे कम विकसित देश, चारों ओर से जमीन से घिरे विकासशील देश और छोटे द्वीप विकासशील राज्य गरीबी उन्मूलन में लगातार प्रगति कर रहे हैं। हालाँकि, असमानता अभी भी बनी हुई है और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं और अन्य संपत्तियों तक पहुंच में बड़ी असमानताएँ बनी हुई हैं।

ब्रिक्स देशों के मध्य आर्थिक असमानता का एक आर्थिक विश्लेषण

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है। यह शब्द शुरुआत में 2001 में गोल्डमैन सॉक्स के अर्थशास्त्री जिम ओश नील द्वारा BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) के रूप में बनाया गया था। उनका मानना था कि 2050 तक चार ठत्प्ब् अर्थव्यवस्थाए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में जोड़ा गया था। BRIC (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) देशों के नेता पहली बार जुलाई 2006 में 18 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिले। कुछ ही समय बाद, सितंबर 2006 में, समूह को औपचारिक रूप दिया गया। उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, – पहला BRIC शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद BRIC समूह का नाम बदलकर BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) कर दिया गया। तदनुसार, दक्षिण अफ्रीका ने 14 अप्रैल 2011 को सान्या, चीन में आयोजित हुए तीसरे BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह

है, जिसमें दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी शामिल है। दुनिया की जीडीपी का 24 प्रतिशत और विश्व व्यापार में 16 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। ब्रिक्स देश वर्षों से वैश्विक आर्थिक विकास के मुख्य इंजन रहे हैं।

देशों के बीच सामाजिक और स्वास्थ्य असमानताएँ

ब्रिक्स देशों में से प्रत्येक देश में आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापा जाता है और आय असमानता को गिनी गुणाक के रूप में मापा जाता है। 1990 और 2010दोनों में, रूसी संघ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी और भारत की सबसे कम। हालाँकि इन दोनों देशों के बीच आय में पूर्ण असमानता 1990 और 2010 के बीच बदल गई, उनके बीच सापेक्ष असमानता 5.9 से गिरकर 2.8हो गई। 1990 और 2010 के बीच, चीन ने सबसे अधिक आय वृद्धि (300 प्रतिशत) का अनुभव किया। हालाँकि, उस अवधि के दौरान, चीन ने भी आय असमानता में सबसे अधिक वृद्धि का अनुभव किया और इसका गिनी गुणांक 32.7 से बढ़कर 47.8 हो गया। रूसी संघ ने आय असमानता में और भी अधिक प्रतिशत वृद्धि का अनुभव किया, क्योंकि इसी अवधि में इसका गिनी गुणांक 25.9 से बढ़कर 42.2 हो गया। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश था जिसने 1990 और 2010 के बीच अपने गिनी गुणांक में कमी देखी थी। इन अस्थायी परिवर्तनों के बावजूद, 1990 और 2010 दोनों में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक आय–असमानता वाले देश थे। असमानता के समान पैटर्न अन्य सामाजिक चरों में भी देखे गए जिनकी हमने जांच की (तालिका नंबर एक) सामान्य तौर पर, रूसी संघ ने सबसे अनुकूल स्थिति दिखाई और भारत ने सबसे कम अनुकूल स्थिति दिखाई। उदाहरण के लिए, 1990 और 2009 में, 25–34वर्ष की आयु की एक महिला द्वारा शिक्षा में बिताए गए वर्षों की औसत संख्या भारत की तुलना में रूसी संघ में क्रमशः 4–और 2.5 गुना अधिक थी। हालाँकि, 2010 में 25–34 वर्ष की आयु वाली एक भारतीय महिला को 1990 में समान आयु वाली भारतीय महिला की तुलना में शिक्षा में बहुत लंबी अवधि का अनुभव होने की संभावना थी–5.6 बनाम 2.9 वर्ष। जहां तक बेहतर पानी और स्वच्छता तक पहुंच का सवाल है, 1990 और 2010 के बीच पूर्ण और सापेक्ष असमानताएं कम हो गईं एक प्रभाव जो विशेष रूप से चीन में स्पष्ट था। 2010 तक, भारत में खुले में शौच का प्रचलन अधिक रहा, लेकिन अन्य चार ब्रिक्स देशों में यह अपेक्षाकृत कम हो गया था।

1990 और 2010 दोनों में, ब्रिक्स के बीच कुल स्वास्थ्य असमानताएँ थी। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में अधिकतम पूर्ण असमानता 1990 में 9वर्ष से बढ़कर भारत और रूसी संघ के बीच 2010 में 20 वर्ष– चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो गई। दक्षिण अफ्रीका में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 1990की तुलना में 2010 में 6.6 वर्ष कम थी। रूसी संघ में, 2010 में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 1990 के समान थी। हालांकि, चीन, ब्राजील और भारत में, औसत जीवन प्रत्याशा 2010 में जन्म के समय 1990 की तुलना में क्रमशः 5.4, 6.5 और 7.0 वर्ष अधिक थे बीमारी के बोझ में देशों के बीच असमानताएं– विशेष रूप से संचारी रोगों के कारण होने वाले बोझ में आम तौर पर हमारे अध्ययन की अवधि में बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, संक्रामक रोगों से होने वाली हानि DALY में सापेक्ष असमानता भारत और रूसी संघ के बीच 1990 में 6.9 से बढ़कर

2010 में दक्षिण अफ्रीका और चीन के बीच 12.4 हो गई। विश्व की शिशु मृत्यु दर की औसत दर 1990 और 2010 के बीच धीरे–धीरे गिर गई, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 36 से 17 शिशु मृत्यु, इसी अवधि में, भारत और रूसी संघ में शिशु मृत्यु दर की दर में बहुत समान प्रवृत्ति देखी गई–हालांकि दर्ज किए गए मूल्य क्रमशः वैश्विक मूल्यों के उच्चतम और निम्नतम चतुर्थक में थे। ब्राजील और चीन में दर्ज की गई संबंधित दरें वैश्विक औसत मूल्यों की तुलना में अधिक तेजी से गिरीं। ये दरें 1990 में वैश्विक औसत से ऊपर शुरू हुई लेकिन 2010 में इससे नीचे आ गईं। दक्षिण अफ्रीका में, शिशु मृत्यु दर में 1996 के बीच वृद्धि हुई जब दर वैश्विक औसत मूल्य के करीब थी और 2004 जब यह दरवैश्विक औसत मूल्य के काफी ऊपर थी।

निष्कर्ष

ब्रिक्स के बीच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में कुल असमानताएं 1990 और 2010के बीच पूर्ण रूप से कम हो गई लेकिन सापेक्ष रूप से बढ़ गई। मातृ मृत्यु दर में पूर्ण असमानताएं 1990 में भारत और रूसी संघ के बीच प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 526 अतिरिक्त मातृ मृत्यु से घटकर 2010 में दक्षिण अफ्रीका और रूसी संघ के बीच प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 266 ऐसी मृत्यु हो गईं। 1990 में, चीन और भारत दोनों में मातृ मृत्यु दर का स्तर 2010 में दर्ज मूल्यों से तीन गुना अधिक था। जब हमने 1990 में शिशु और बाल मृत्यु दर की पूर्ण असमानताओं की जांच की, तो हमने पाया कि– प्रति 1000 जीवित जन्म वहीं 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की 58 अतिरिक्त मौतें हुई और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 87 अतिरिक्त मौतें हुई। हालाँकि, 2010 में, संबधित मान कम थे, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर क्रमश 38 और 51 अतिरिक्त मौतें। 1990 और 2010दोनों में, शिशु और बाल मृत्यु दर दोनों में सबसे बड़ा अंतर भारत और रूसी संघ के बीच था। 1990 और 2010 के बीच, ब्राजील ने शिशु (69 प्रतिशत) और बाल मृत्यु दर (71 प्रतिशत) में सबसे बड़ी कमी दर्ज की, इसके बाद चीन (क्रमशः 65 प्रतिशत और 67 प्रतिशत) का स्थान रहा।

संदर्भ

1. बोहरे, आर.के. (2002). भारत में ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी. उत्तरी दिल्ली।
2. अग्रवाल, ए.एन. (1997). इंडियन इकोनॉमी. वीकली प्रकाशकः नई दिल्ली।
3. https://data-oecd-org/inequality/income&vlekurk-html.
4. झिंगन, एम.एल. (1998). अर्थशास्त्र विकास और योजना. वृंदा पब्लिकेशन प्रा. लिमिटेड़ः दिल्ली. पृष्ठ **422.**
5. https://www-undp-org/sustainable&developekufld&y{;/de&vlekurk,¡A Mksfefud lkYokrksj] varjkZ"Vªh.
6. https://brics2021-gov-in/brics/public/ uploads/docpdf/getdocu&72-pdf.
7. https://www-unep org/eÛplore&topics/sustainable&development&goals/ why&do&sustainable& development&goals&matter/goal&10A.